हिंदी दैनिक
न्यूज़ वायरस

दून में बिना मास्क निकले तो भरना होगा 500 का जुर्माना 2

वर्ष : 10 अंक : 272 | बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर ज़ोरदार प्रहार

कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल हटाये गए, तत्कालीन पीसीसीएफ जे. एस.सुहाग और डीएफओ किशन चंद निलंबित

सवाल जिनके जवाब अनसुलझे

1. सम्पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित फिर भी तत्कालीन पीसीसीएफ जे. एस.सुहाग निलंबित और निदेशक मुख्यालय से अटैच, आखिर कैसे
2. कपिल जोशी और अमित वर्मा की 500 पेजों की जांच रिपोर्ट में कौन कौन दोषी,पता नही
3. एक ही तारीख में एक ही अधिकारी द्वारा फाउंडेशन से दो करोड़ संबंधित कार्य के लिए अवमुक्त और उसी दिन शिकायती पत्र प्रेषित,विरोधाभास क्यों
4. आखिर क्यों सीईसी ने वरिष्ठ अधिकारियो को तलब किया,29 अप्रैल को सीईसी के समक्ष पेश होना है मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक को
5. तत्कालीन डीएफओ अखिलेश तिवारी ने इस पूरे प्रकरण में क्या क्या भूमिका निभाई,कितने समय चार्ज उनके पास रहा और क्या क्या कार्य संपादन में उनकी भूमिका रही और किशनचंद को विरासत में क्या कुछ सौंपा
6. शासन के आला अधिकारियों ने किसे किसे और क्यों आशीर्वाद दिया, मौन मंथन की वजह

सलीम सैफी
न्यूज वायरस नेटवर्क

19 अप्रैल को न्यूज़ वायरस समूह ने अपने हिंदी दैनिक अखबार में एक खबर प्रकाशित की और बुधवार तक मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़ी कार्यवाही का पत्र जारी हो गया है।

खबर का बड़ा असर हुआ है उत्तराखंड वन विभाग में चल रहे बड़े गड़बड़झाले से जुड़ी जांच के मामले में , जहां दो आईएफएस अफसर सस्पेंड किये गए हैं तो वही कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।

आपको बता दें कि न्यूज़ वायरस हिंदी दैनिक ने जिम कॉर्बेट में हुए विवादित निर्माण कार्य और तमाम अनियमितताओं से जुड़ी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी । जिसका संज्ञान लेते हुए अब वाले डीएफओ किशनचंद को भी सस्पेंड किया गया है।

लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क पर बनी इस चर्चित फिल्म की कहानी के मुख्य सूत्रधार को अटैच करके बड़ी राहत दे दी गयी है लेकिन क्यों और किसके इशारे पर, ये रहस्य है। सरकार ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल को देहरादून वन मुख्यालय में अटैच कर दिया है। बीते दिनों पाखरो रेंज में अवैध निर्माण और कटान मामले में पूर्व सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए थे और इस मामले की जांच भी की जा रही थी। खास बात यह है कि अब इस मामले में गलत कार्यों की पुष्टि होने पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा अपने धाकड़ अंदाज में बड़ी कारवाई की गई है।

यह है मामला : कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के अंतर्गत पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण के लिए पूर्व में स्वीकृति से अधिक पेड़ों का कटान कर दिया गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में सड़क, मोरघट्टी व पाखरो वन विश्राम गृह परिसर में भवन के अलावा जलाशय का निर्माण भी कराया गया।

इन कार्यों के लिए पीसीसीएफ एस सुहाग से कोई वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी क्योंकि ये अधिकार सिर्फ पार्क निदेशक के कलम में होता है। इस संबंध में मिली शिकायतों के बाद गत वर्ष जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, तब मामला प्रकाश में आया।

एनटीसीए ने शिकायतों को सही पाते हुए हैं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की। इससे विभाग में हड़कंप मचा, लेकिन शुरुआत में केवल रेंज अधिकारी को हटाया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो गत वर्ष 27 नवंबर को शासन ने तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग से यह जिम्मेदारी वापस ले ली थी।

साथ ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के डीएफओ किशन चंद को विभाग प्रमुख कार्यालय से संबद्ध किया गया। यद्यपि, सीटीआर के निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई न होने से प्रश्न उठ रहे थे। यह प्रकरण उच्च न्यायालय में भी चल रहा है।

विभागीय जांच में अनियमितता की पुष्टि : वन विभाग के मुखिया ने कुछ समय पहले इस प्रकरण की जांच के लिए पांच सदस्यीय विभागीय दल गठित किया। दल ने अपनी रिपोर्ट में कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में हुए निर्माण कार्यों और टाइगर सफारी के लिए पेड़ कटान में गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय व आपराधिक अनियमितता परिलक्षित होने की पुष्टि की।

लेकिन इस कार्यवाही के साथ ही कुछ अनुत्तरित सवाल है जो हमारे सामने खड़े हो गए हैं । सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी कपिल जोशी और अमित वर्मा की अगुवाई में शासन ने जो टीम बनाई थी उस टीम ने 500 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी जो कभी बाहर नही आई और जिसे नजरअंदाज किया गया है। मौजूदा कार्यवाही के बारे में सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त यह सारे मामले चल रहे थे उस वक्त डीएफओ कालागढ़ के पद पर अखिलेश

❖ (शेष पेज-2 पर)

उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी और कड़ी कार्यवाही कर दी है। पहले पढ़ लीजिए पत्र में क्या लिखा है।

ये है खबर का पूरा ब्यौरा : अब समझिए कि बुधवार शाम क्या हुआ है , शासन से जारी इस आदेश के पीछे एक लंबी स्क्रिप्ट लिखी गयी है। जिसके बाद धामी सरकार ने वन विभाग में अवैध निर्माण समेत अनियमितताओं के मामले में तीन IFS अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। सरकार ने दो आईएफएस अधिकारियों को जहां निलंबित किया है. वहीं, एक आईएफएस अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया है।

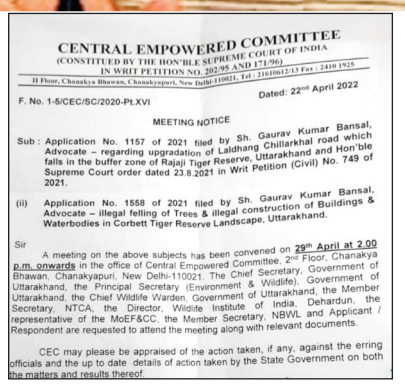

आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर अवैध निर्माण समेत अनियमितताओं के मामले में सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में कैंपा की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख वन संरक्षक जेएस सुहाग को जहां निलंबित किया गया है तो वहीं पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में चर्चाओं में रहने

CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE
(CONSTITUTED BY THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA IN WRIT PETITION NO. 202/95 AND 171/96)
II Floor, Chanakya Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi-110021, Tel : 21610612/13 Fax : 2410 1925

F. No. 1-5/CEC/SC/2020-Pt.XVI — Dated: 22nd April 2022

MEETING NOTICE

Sub : Application No. 1157 of 2021 filed by Sh. Gaurav Kumar Bansal, Advocate – regarding upgradation of Laldhang Chillarkhal road which falls in the buffer zone of Rajaji Tiger Reserve, Uttarakhand and Hon'ble Supreme Court order dated 23.8.2021 in Writ Petition (Civil) No. 749 of 2021.

(ii) Application No. 1558 of 2021 filed by Sh. Gaurav Kumar Bansal, Advocate – illegal felling of Trees & illegal construction of Buildings & Waterbodies in Corbett Tiger Reserve Landscape, Uttarakhand.

Sir

A meeting on the above subjects has been convened on **29th April at 2.00 p.m. onwards** in the office of Central Empowered Committee, 2nd Floor, Chanakya Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi-110021. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, the Principal Secretary (Environment & Wildlife), Government of Uttarakhand, the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, the Member Secretary, NTCA, the Director, Wildlife Institute of India, Dehardun, the representative of the MoEF&CC, the Member Secretary, NBWL and Applicant / Respondent are requested to attend the meeting along with relevant documents.

CEC may please be appraised of the action taken, if any, against the erring officials and the up to date details of action taken by the State Government on both the matters and results thereof.

. किसी भी कार्य हेतु बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के किसी प्रकार का वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

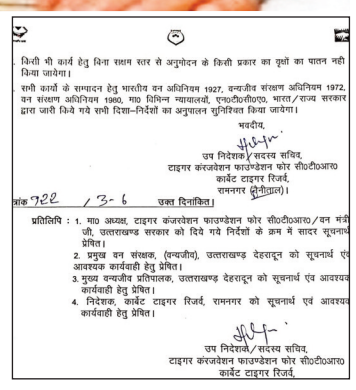

. सभी कार्यो के सम्पादन हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, मा0 विभिन्न न्यायालयों, एन0टी0सी0ए0, भारत/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
उप निदेशक/सदस्य सचिव,
टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0टी0आर0
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 922 / 3-6 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. मा0 अध्यक्ष, टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0टी0आर0/वन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को दिये गये निर्देशों के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव), उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

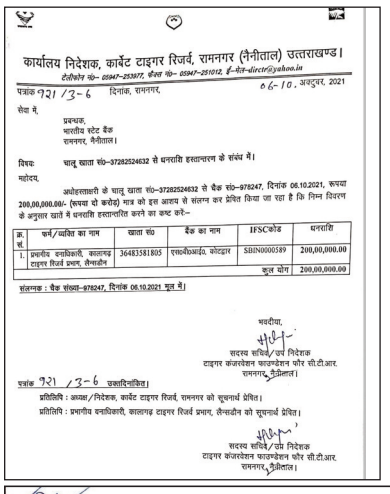

उप निदेशक/सदस्य सचिव,
टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0टी0आर0
कार्बेट टाइगर रिजर्व,

कार्यालय निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
टेलीफोन नं0– 05947–253977, फैक्स नं0– 05947–251012, ई–मेल–directr@yahoo.in

पत्रांक 921 / 3-6 दिनांक, रामनगर, 06-10. अक्टुबर, 2021

सेवा में,
प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
रामनगर, नैनीताल।

विषयः चालू खाता सं0–37282524632 से धनराशि हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के चालू खाता सं0–37282524632 से चैक सं0–978247, दिनांक 06.10.2021, रूपया 200,00,000.00/- (रूपया दो करोड़) मात्र को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि निम्न विवरण के अनुसार खातें में धनराशि हस्तान्तरित करने का कष्ट करें:–

क्र. सं.	फर्म/व्यक्ति का नाम	खाता सं0	बैंक का नाम	IFSCकोड	धनराशि
1.	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन	36483581805	एस0बी0आई0, कोटद्वार	SBIN0000589	200,00,000.00
				कुल योग	200,00,000.00

संलग्नक : चैक संख्या–978247, दिनांक 06.10.2021 मूल में।

भवदीया,
सदस्य सचिव/उप निदेशक
टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फौर सी.टी.आर.
रामनगर, नैनीताल।

पत्रांक 921 / 3-6 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव/उप निदेशक
टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फौर सी.टी.आर.
रामनगर, नैनीताल।

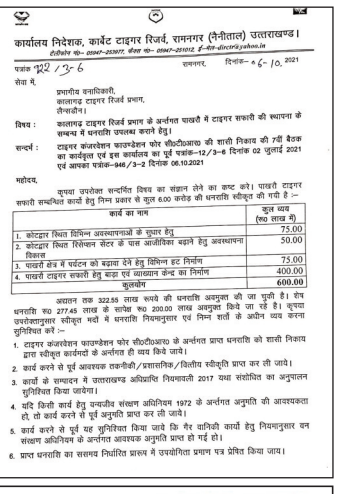

कार्यालय निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
टेलीफोन नं0– 05947–253977, फैक्स नं0– 05947–251012, ई–मेल–directr@yahoo.in

पत्रांक 922 / 3-6 रामनगर, दिनांक– 06-10. 2021

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषय : कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के अन्तर्गत पाखरौ में टाइगर सफारी की स्थापना के सम्बन्ध में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु।

सन्दर्भ : टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0टी0आर0 की शासी निकाय की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त एवं इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक–12/3–6 दिनांक 02 जुलाई 2021 एवं आपका पत्रांक–946/3–2 दिनांक 06.10.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषय का संज्ञान लेने का कष्ट करे। पाखरौ टाइगर सफारी सम्बन्धित कार्यो हेतु निम्न प्रकार से कुल 6.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है :–

कार्य का नाम	कुल व्यय (रू0 लाख में)
1. कोटद्वार स्थित विभिन्न अवस्थापनाओं के सुधार हेतु	75.00
2. कोटद्वार स्थित रिसेप्शन सेंटर के पास आजीविका बढ़ाने हेतु अवस्थापना विकास	50.00
3. पाखरौ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न हट निर्माण	75.00
4. पाखरौ टाइगर सफारी हेतु बाड़ा एवं व्याख्यान केन्द्र का निर्माण	400.00
कुलयोग	600.00

अद्यतन तक 322.55 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष धनराशि रू0 277.45 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख अवमुक्त किये जा रहे है। कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृत मदों में धनराशि नियमानुसार एवं निम्न शर्तो के अधीन व्यय करना सुनिश्चित करें :–

1. टाइगर कंजरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0टी0आर0 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को शासी निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यमदों के अन्तर्गत ही व्यय किये जाये।
2. कार्य करने से पूर्व आवश्यक तकनीकी/प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
3. कार्यो के सम्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथा संशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि किसी कार्य हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अनुमति की आवश्यकता हो, तो कार्य करने से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।
5. कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि गैर वानिकी कार्यो हेतु नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त हो गई हो।
6. प्राप्त धनराशि का ससमय निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।

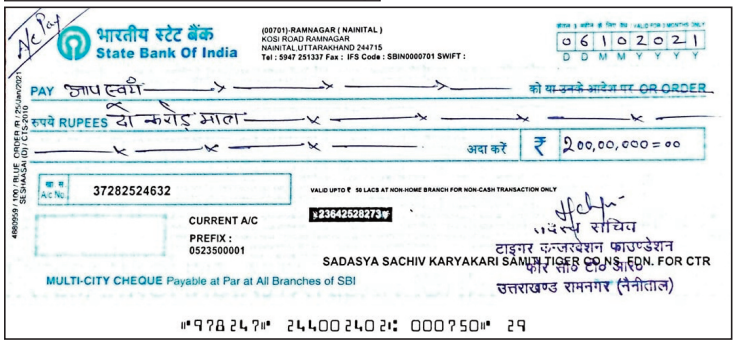

A/c Pay
भारतीय स्टेट बैंक State Bank Of India
(00701)-RAMNAGAR (NAINITAL)
KOSI ROAD RAMNAGAR
NAINITAL,UTTARAKHAND 244715
Tel : 5947 251337 Fax : IFS Code : SBIN0000701 SWIFT :
06102021
PAY आप स्वयं को या उनके आदेश पर OR ORDER
रुपये RUPEES दो करोड़ मात्र
अदा करें ₹ 200,00,000=00
खा. सं. A/c No. 37282524632
VALID UPTO ₹ 50 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY
CURRENT A/C
PREFIX : 0523500001
सदस्य सचिव टाइगर कन्जरवेशन फाउण्डेशन फोर सी0 टी0 आर0 उत्तराखण्ड रामनगर (नैनीताल)
SADASYA SACHIV KARYAKARI SAMITI TIGER CONS. FDN. FOR CTR
MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI
⑈978247⑈ 244002402⑆ 000750⑈ 29

पीएम मोदी का सपना धामी करेंगे सच

अत्याधुनिक सप्रिचुअल केंद्र बन रहा बद्रीनाथ धाम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश दुनिया के तीर्थयात्रिओं को देवभूमि आने पर्व एक बदले हुए अद्भुत बद्रीनाथ धाम का दर्शन हो सकेगा। देवभूमि से गहरी आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान का तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की योजना है कि बदरीनाथ धाम को भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर स्मार्ट सप्रिचुअल हिलटाउन के रूप में विकसित किया जाये । बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान का पूरा नक्शा गुजरात की कंपनी आईएनआई ने डिजाइन किया है। इसी नक्शे के आधार पर पहले फेज के नव निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है।

ऐसे में साल 2023 में जब बदरीनाथ की यात्रा शुरू होगी तो बदरीनाथ धाम किसी स्मार्ट आध्यात्मिक स्थान से कम नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदरीनाथ में होने जा रहे कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बदरीनाथ धाम को ठीक वैसे ही विकसित किया जा रहा है, जैसे कशी विश्वनाथ कॉरिडोर को किया गया है।

आधुनिकीकरण का बजट है 277 करोड़ - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को विश्व पटल पर विकसित करके एक नई पहचान देना चाहते हैं। जिससे दोनों ही धामों में आने वाला हर

एक श्रद्धालु वहां की आध्यात्मिकता को हमेशा अपनी यादों में रखे। पीएम की भावना को समझते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार भी तेज़ गति से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रही है जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री धामी स्पॉट्स का दौरा कर ग्राउंड पर मुआयना कर निर्देश भी दे रहे हैं। बदरीनाथ धाम में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है और इस भूमि अधिग्रहण में तकरीबन 22 सरकारी भवनों के साथ-साथ अन्य दूसरे भवनों का भी अधिग्रहण किया गया है। इस मामले में अभी तक 33 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है।

धाम में वन-वे लूप रोड का पहाड़ी शैली के पत्थर से निर्माण होगा. इसमें लगभग 700 मीटर सड़क बनाई जाएगी। अराइवल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा, जहां यात्रा टिकट की बुकिंग, होटलों की जानकारी जैसी सुविधाएं तीर्थ यात्रियों को दी जाएगी। बदरीनाथ में स्थित शेष नेत्र झील और बदरीश झील का सौंदर्यीकरण होगा। ये दोनों झीलें लगभग 300 मीटर तक फैली हैं, बदरीनाथ धाम में स्थित अस्पताल का विस्तारीकरण होगा, जिससे कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को अच्छा उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही धाम में सभी घाटों का सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य किया जाएगा।

बदरीनाथ धाम के इस मास्टर प्लान के तहत आने वाले 100 सालों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस धाम को विकसित किया जा रहा है। इसी आधार पर बुनियादी ढांचों के विकास के साथ-साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। तो अगर आप कुछ साल या महीने बाद बद्रीनाथ धाम आएंगे तो आपको एकदम बदली हुयी तस्वीर नज़र आएगी और ेल अलग ही भव्यता का अनुभव होगा।

Corona is back ! दून में बिना मास्क निकले तो भरना होगा 500 का जुर्माना, डीएम का सख्त आदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जिस तरह से देश में कोरोना ने फिर से रफ़्तार पकड़ी है उसके बाद देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पहले स्कूल की छात्रा कोरोना संक्रमित हुयी उसके बाद सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को कोरोना ने जकड़ लिया है। इस घटा के बाद जिलाधिकारी और पुलिस-प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला वसूला जाए जिससे लोग जागरूक हों और नियमों का पालन करें।

आपको बता दें कि पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है और मसूरी धनौल्टी चकराता नैनीताल सहित तमाम हिल स्टेशनों पर देश भर से सैलानी बड़ी संख्या में आने भी लगे हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते हुए मामले सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन रहा है।

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। जबकि, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं तो वहीं, एक्टिव केस

की संख्या 87 है... पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है... प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.04% है... जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में देहरादून में 13 नये मरीज मिले हैं...

पर्यटन व्यवसायियों के साथ साथ प्रदेश की लाखों लोगों के आर्थिकी का ये सबसे व्यस्त समय होता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का खौफ फिर सर उठाने लगा है। उसके बाद आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट हो तो कोई हैरानी नहीं होगी।

पेज एक का शेष

सीएम धामी का भ्रष्ट्राचार पर....

तिवारी कार्यरत थे , बावजूद इसके उन्हें इस मामले में पूरी तरह से अलग-थलग करते हुए क्लीन चिट दे दी गई। सवाल यह भी उठता है कि जब डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास ही सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार थे तो उन्हें संरक्षण देते हुए मुख्यालय से अटैच कर क्यों बचाया गया ? उच्च स्तरीय सूत्रों की माने तो आनन-फानन में की गई इस कार्यवाही का मकसद दिल्ली में 29 अप्रैल को सीईसी की होने वाली पेशी से आला अधिकारियों और सरकार को तो बचाना है ही बल्कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्ट्राचार के विरुद्ध सख्त रुख भी है क्योंकि धाकड़ धामी किसी भी स्तर पर,किसी भी अधिकारी द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के अभियान में जुटे है मगर फिर इस बड़ी कार्यवाही में भी शासन के अधिकारियों द्वारा किसी को तो बचा ही लिया गया है वो भी किसी ओर को बलि का बकरा बना कर इतिश्री कर ली गई ।

लेकिन इस कार्यवाही के बाद जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है । क्या सारे गैर जिम्मेदार क्रियाकलापों और अनियमितताओं के लिए शासन ने इंसाफ की नज़र से सही चेहरों को चुना है ? आज नही तो कल शासन के दोषी भी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के समक्ष बेनकाब हो ही जाएंगे, सीईसी जो करेगी वो तो करेगी ही?????

पर्यटन मंत्री महाराज ने किया औचक निरीक्षण, जमकर लगाई फटकार; फोन उठाने की दी हिदायत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क (आशीष तिवारी)

पर्यटन प्रदेश के सबसे अनुभवी और सीनियर धर्मार्थ कार्य मंत्री सतपाल महाराज का गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। कार्यशैली में लापरवाही हो या आदेशों को अनसुना करना हो जैसे ही ये सच महाराज के सामने उजागर होता है उनका गुस्सा सामने वाले पर बरस ही पड़ता है।

कुछ ऐसा ही तब हो गया जब श्री बदरीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री सीधे कार्यालय का रियलिटी चेक करने पहुँच गए। लगातार मीटिंगों और आदेशों में पर्यटन मंत्री ने नसाफ किया है कि चार धाम यात्रा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी अधिकारी-कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जायेगी।

अब ऐसे में जब महाराज का काफिला चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त करने की सबसे ज़िम्मेदार संस्था के दफ्तर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को से कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। दो लाख से अधिक यात्री अभी तक अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इसलिए हमें दिन-रात काम करना पड़ सकता है। उन्होने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का शत प्रतिशत पालन करें।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यह यात्रा हमारे राज्य के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी है। इसलिए यात्रा को हर हाल में सफल बनाने का प्रयास करना है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कड़े और तेज़ स्वर में स्पस्ट बोलते हुए कहा कि हमें लोगों की बातों को सुनना है, मोबाइल फोन उठना है और यदि किसी कारणवश हम फोन नहीं उठा सके तो वापस कॉल करना है। इसी प्रकार कुछ प्रमुख बातों को हमें ध्यान में रखना होगा ताकि हमारी यात्रा ठीक से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी इस प्रकार का औचक निरीक्षण करूंगा और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दाखिल की जाएगी।

इस दौरान श्री बदरीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेन्द्र अजय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी. सिंह, सदस्य पुष्कर जोशी भी मौजूद थे।

प्रदेश में बनेगी संस्कृत शिक्षा की नियमावली : डॉ0 धन सिंह रावत

अधिकारियों को दिये एक माह के अंदर ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क (आशीष तिवारी)

राज्य में संस्कृत शिक्षा की नियमावली तैयार कर विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जायेगा। राज्य में स्थापित संस्कृत परिषद, संस्कृत आकदमी व संस्कृत निदेशालय की जिम्मेदारियां नियम की जायेगी। इसके साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देश के अन्य राज्यों में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अभिनव कार्यों का अध्ययन कर नई नियमावली तैयार करें। इसके लिए उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को तीन सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश विभागीय सचिव को दिये। उन्होंने कहा कि समिति एक माह के भीतर नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसका अध्ययन करने के पश्चात नियमावली को अंतिम रूप दिया जायेगा।

विभागीय मंत्री ने कहा कि संस्कृत के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी। विभागीय मंत्री द्वारा अधिकारियों को संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत सौ दिनों का टारगेट तय करने के निर्देश दिये गये। जिसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की एकरूपता लाने के लिए शैक्षिक पंचांग लागू करने, राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का निर्माण एवं विस्तार करने, ज्योतिष वास्तु, पुरोहित्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करने, अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन आयोजित करने, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता सहित गीता मास महोत्सव, कालिदास सम्पात महोत्सव, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम शामिल करने को कहा गया। डॉ0 रावत ने अधिकारियों को राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं एवं वित्तीय सहायता के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

बैठक में सचिव संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश कुमार, संयुक्त सचिव बी.पी. सिंह, निदेशक संस्कृत शिक्षा एस.पी. खाली, सचिव संस्कृत शिक्षा परिषद भूपेन्द्र सिंह नेगी, उप सचिव प्रदीप नौटियाल, अनुसचिव अरूण कुमार, वित्त अधिकारी संस्कृत अकादमी कन्हैया राम कार्की, अनुभाग अधिकारी संजय कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम योगी आदित्यनाथ तीन मई को आएंगे उत्तराखंड : धन सिंह रावत

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताय है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। 3 मई को प्रस्तावित कार्यकर्म के मुताबिक योगी अपने गुरु की प्रतिमा का आवरण करने यमकेश्वर डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना जांच दोगुनी की जाएगी। राज्य में आने वाले लोगों को भी जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। सर्तकता के साथ सभी को एहतियात रखने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर हर स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटी है। वहीं उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में बताया।

उत्तराखंड का हर गाँव बनेगा स्मार्ट विलेज : सतपाल महाराज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

राज्य में पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष निरन्तर इजाफा हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटक स्थलों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक जिला पंचायत पर्यटक स्थलों के समीप स्थान चिन्हित करते हुए वहाँ कार पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ कन्जेक्सन टैक्स लागू करें।

ये बात प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बुद्धवार को पंचायतीराज निदेशालय, डांडालखौड में पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष निरन्तर इजाफा हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटक स्थलों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक जिला पंचायत पर्यटक स्थलों के समीप स्थान चिन्हित करते हुए 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से वहाँ कार पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाएँ।

उन्होने कहा कि राज्य के अधितर युवा सेना एवं पुलिस की तैयारी करते हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए जिम आदि की व्यवस्था नहीं है। अतः वित्त आयोग के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त धनराशि से प्रथमिकता के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में एक जिम स्थापित किया जाए। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य की कुछ ग्राम पंचायतें स्वयं के आय कर रही हैं, उनका अनुसरण करते हुए अन्य ग्राम पंचायतें भी स्वयं के आय के स्रोतों को बढ़ायें और इसके लिए संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी सभी पंचायतों को सुझाव जारी करें। सतपाल महाराज ने कहा कि जिन पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटक अधिक मात्र में आते हैं वहाँ जिला पंचायतें कन्जेक्सन टैक्स लागू करें। उन्होने सुझाव दिया कि प्रारम्भ में उक्त टैक्स अवकाश दिवसों में लागू किया जा सकता है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज विभागीय अधिकारियों से कहा कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक गाँव को स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक गाँव में कम्प्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में स्थिति सभी विद्यालयों, आँगनवाडी केन्द्रों, पंचायत घरों एवं अन्य सामुदायिक भवनों में पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाय। उन्होने निर्देश दिये कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उक्त व्यवस्था का स्थानीय निरीक्षण कर संबंधित विभाग एवं निदेशालय को अवगत करायेंगे। विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि पंचायतों में किसी भी सामुदायिक भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उक्त भवन भविष्य में बहुउददेशिय रूप में उपयोग में लाया जा सके। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रत्येक माह में विभाग के कार्यों की प्रगति के संबंध में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

बैठक के दौरान नितेश कुमार झा, सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, बंशीधर तिवारी, निदेशक पंचायतीराज, उपनिदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी सहित राज्य के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं निदेशालय पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण के अधिकारी उपस्थित थे।

एसडीएम हादसा मामले की मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर हाज़िर हो : विनय शंकर पांडे, डीएम हरिद्वार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि रुड़की -लक्सर मार्ग पर तहसील रूड़की अन्तर्गत सोलानी पुल के समीप संगीता कन्नौजिया, उप जिलाधिकारी, लक्सर के शासकीय वाहन की एक डम्पर से टक्कर हो जाने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तथा उक्त दुर्घटना के दौरान गोविन्द कुमार, वाहन चालक (पी०आर०डी०) की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

इस दुर्घटना में संगीता कन्नौजिया, उप जिलाधिकारी, लक्सर गम्भीर रुप से घायल हो गई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश, देहरादून के लिए डॉक्टरों के परामर्श पर रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी विनय शंकर ने यह भी बताया कि इस घटना में दिवंगत वाहन चालक (पी०आर०डी०), गोविन्द कुमार उर्फ गोविन्दा के मृत्यु एवं संगीता कन्नौजिया, उप जिलाधिकारी, लक्सर के गंभीर रूप से घायल होने संबंधी समस्त घटनाक्रम की विस्तृत मजिस्ट्रीयल जांच कराया जाना बेहद ज़रूरी है।

जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस घटनाक्रम की मजिस्ट्रीयल जांच किए जाने के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की जिला हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा इस घटनाक्रम की तत्परता से तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौके पर जिसने भी इस घटना को घटित होना देखा गया हो, के लिखित एवं मौखिक बयान अंकित करते हुए विस्तृत एवं सुस्पष्ट जांच करते हुए अपनी मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश संयुक्त मजिस्ट्रेट को दिये गये हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पॉक्सो वॉरियर्स को सम्मानित किया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा पोक्सो अधिनियम पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पॉक्सो एक्ट पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया और पॉक्सो वॉरियर्स को सम्मानित भी किया ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बच्चों में रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने में उनके माता, पिता और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौनिहालों से जुड़ी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन नियमित होने चाहिए। जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश नहीं मिलती, उनके लिए समाज को आगे आना चाहिए। सरकार सबके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को भयमुक्त वातावरण मिलेगा तो उनका भविष्य सकारात्मक दिशा में जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए जो कानून बने हैं, उनका सख़्ती से पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां जागरूकता बढ़ेगी वहीं विशेषज्ञों के मंथन से हमारे भविष्य हमारे बच्चों को रचनात्मक बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सेना और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम में अवश्य

प्रतिभाग करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के ध्येय वाक्य से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाएँ। बाल अधिकारों की आम जन तक जागरूकता के लिए इस संबंध में समय-समय पर विधिक शिविर भी आयोजित किए जाएँ।

कार्यशाला में बतौर विशिष्ट अतिथि महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के नौनिहालों के साथ सरकार हर तरीके से खड़ी है कोरोना काल में अपने परिजनों को गंवा चुके बच्चों को वात्सल्य योजना के ज़रिए सरकार सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वात्सल्य योजना देश में सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। डीजीपी अशोक कुमार ने पोक्सो एक्ट संबंधित विस्तृत जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, विधि विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

ब्रिडकुल पर फूटा मंत्री जी का गुस्सा, अफसर पर बरसे; तुरंत रुकवाया निर्माण कार्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आईएसबीटी के समीप निर्माणाधीन रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप में गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरभाष पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को यह निर्देश दिए।

बुधवार को बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यटन विभाग और ब्रिडकुल के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। उन्होंने आईएसबीटी के समीप बन रहे रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप के संदर्भ में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन में गुणवत्ता की कमी होने की लगातार शिकायत मिल रही है। इस मामले में पर्यटन विभाग के अधिकारी बंगले झांकने लगे। संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते मंत्री जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने पर्यटन अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और बैठक के बीच में ही पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को फ़ोन घुमा दिया

गुस्साए मंत्री जी ने सचिव दिलीप जावलकर को निर्माणाधीन रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप कार्य को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय पर्यटन अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। पर्यटन सचिव को कहा कि सरकार की रूपयों की हीलाहवाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।आपको बता दें कि आईएसबीटी के समीप पर्यटन विभाग की ओर से 3.70 हेक्टेअर भूमि पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसकी लागत 14.80 करोड़ रूपए है, जिसकी कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल है। यह कार्य 27 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था, जिसे 23 मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाना था। उक्त कार्य में लगातार गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए है।इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान, अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद, ब्रिडकुल के अधिशासी अभियंता अमित नेगी, अवर अभियंता जसवीर सजवाण मौजूद रहे।

चार धाम की लाइफलाइन रूद्रप्रयाग के जंगलों में आग ही आग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है... जंगलों में लगी आग अब आवासीय क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है.. जिला मुख्यालय से सटे गांवों में जंगलों की आग पहुंच रही है, जिसके बाद ग्रामीण जान पर खेलकर आग बुझाने में लगे हैं... वहीं आसमान में चारो तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है... स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ऐसा लगने लगा है कि वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है...

पहाड़ में बीते कई दिनों से जंगलों में लगी आग ने अब विकराल रूप धारण कर दिया है... इन दिनों जनपद का कोई भी ऐसा जंगल नहीं है जो जलकर राख न हो रहा हो... आग से जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं तो वहीं जंगली जानवरों का जीवन खतरे में पड़ गया है और प्राकृतिक सम्पदा जलकर राख हो रही है... आसमान में छाई धुंध के कारण आम जनता की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं... इस धुंध के कारण जहां सूर्य की रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा है तो वहीं भीषण गर्मी भी पड़ रही है...

पहाड़ों की ऐसी हालत देख कर पर्यावरणविद कहते हैं कि ब्लैक कार्बन के कारण प्रभावित इलाकों में लोगों की आंखों में जलन और खुजली हो रही है... पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है... पौधों में बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं... आंकड़ों में साफ है कि जंगल में आग लगने से तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है और 332.82 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं... यह एक गंभीर चिंता का विषय है, ऐसे में विभाग को गंभीरता दिखते हुए उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के प्रयास करने होंगे...

कोरोना पर पीएम की 24वीं बैठक : टीम भावना के साथ काम करें सभी सीएम : प्रधानमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर ऑनलाइन बैठक की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा, बीते दो वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा, हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें सामूहिक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी यही रहना चाहिए।

चौथी लहार के साथ ही बड़ी मुसीबत स्कूल जा रहे बच्चों पर नज़र आ रही है लिहाज़ा पीएम ने इस तरफ भी अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में कोरोना केस के बढ़ने से कहीं न कहीं अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। बच्चों के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन संतोष की बात है कि बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल रहा है। कल ही छह से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण की अनुमति मिल गई है। पहले की तरह स्कूल में विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी।

डिजिटल प्लेटफोर्म पर जुटे सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दो साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक सुधार किया है। आज कोरोना की जो स्थिति है, उसमें यह जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर किया जाए और पॉजिटिव आने वाले मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजे जाएं। पीएम ने कहा, यह सुनिश्चित करें कि जनता में पैनिक न फैले। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम चलता रहना चाहिए। सारी सुविधाएं संचालित स्थिति में हों, यह भी सुनिश्चित करें। अगर कहीं कोई समस्या है, उसे उच्च स्तर पर सुलझाया जाए।

12 दिन गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस की हवा परखेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा 28 अप्रैल से 12 दिवसीय गढ़वाल मण्डल दौरे की शुरूआत करेंगे। अपने भ्रमण के दौरान माहरा 28 अप्रैल, को मसूरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आन्दोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके उपरान्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से मिलेंगे

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि 12 दिवसीय गढ़वाल मण्डल भ्रमण के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा उत्तरकाशी, टिहरी, पौडी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तथा हरिद्वार में गंगा आरती के साथ ही अपने इस पहले चरण के लम्बे दौरे का समापन करेंगे।

मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा 28 अप्रैल को 14:00 बजे नैनबाग, 16:30 बजे पुरोला में कार्यकर्ताओं से भेंट करने के उपरान्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 धूम सिंह रावत के पैत्रिक गांव छटांगा में उनके निवास पर रात्रि विश्राम करेंगे।

29 अप्रैल को 10:00 बजे बडकोट तथा 14:00 बजे डुण्डा में कार्यकर्ताओं से भेंट करने के उपरान्त अपराह्न 15:00 बजे उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करने के पश्चात ग्राम पंजाला में रात्रि विश्राम करेंगे। 30 अप्रैल को प्रातः 0730 बजे उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मन्दिर में पूजा दर्शन के उपरान्त 10:30 बजे चिन्यालीसौड में कार्यकर्ताओं से भेंट करने के पश्चात 13:00 बजे कण्डीसौड तथा 16:00 बजे चम्बा में कार्यकर्ताओं से भेंट तथा 17:30 बजे पत्रकार वार्ता करने के उपरान्त अमर शहीद श्रीदेव सुमन के गांव जौल के लिए प्रस्थान करेंगे।

1 मई, को 10:30 बजे नई टिहरी तथा अपराह्न 13:30 बजे नरेन्द्रनगर में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त 16:00 बजे ऋषिकेश में पत्रकार वार्ता को संबोधित करने तथा कार्यकर्ताओं से भेंट के पश्चात कोटद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 मई को प्रातः 10:00 बजे कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त 12:00 बजे कोटद्वार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। 13:00 बजे दुगड्डा एवं 13:45 बजे सतपुली में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त पौडी के लिए प्रस्थान करेंगे। 17:00 बजे पौडी में कार्यकर्ताओं से भेंट तथा रात्रि विश्राम करेंगे ।

3 मई, 2022 को प्रातः 10:00 बजे पौडी में पत्रकार वार्ता के पश्चात श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। 12:00 बजे श्रीनगर तथा 16:00 बजे रूद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त कर्णप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। 4 मई 2022 को प्रातः 10:00 बजे कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त 12:00 बजे कर्णप्रयाग में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। 14:00 बजे थराली में कार्यकर्ताओं से संवाद के उपरान्त गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 5 मई को प्रातः 08:00 बजे गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 6 मई, 2022 को प्रातः केदारनाथ धाम में पूर्जा दर्शन के उपरान्त 10:00 बजे गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। गुप्तकाशी में कार्यकर्ताओं से संवाद के उपरान्त रात्रि विश्राम के लिए गोपेश्वर पहुंचेंगे।

7 मई, 2022 को प्रातः 10:00 बजे गोपेश्वर में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त 12:00 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। 14:30 बजे जोशीमठ में कार्यकर्ताओं से भेंट के उपरान्त श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 8 मई को प्रातः श्री बद्रीनाथ धाम में पूर्जा दर्शन के लिए उपरान्त 10:00 बजे हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे तथा दिनांक 9 मई को हरिद्वार में प्रातः गंगा आरती में प्रतिभाग करेंगे। मथुरादत्त जोशी ने कहा कि गढ़वाल मण्डल भ्रमण के उपरान्त शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कुमाऊ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों : सीएम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कोविड-19 के दृष्टिगत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बाद मे सचिवालय में अधिकारियो की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिये कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्णतः अनुपालन करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोरोना की संभावित लहर के दृष्टिगत अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पर्याप्त मेनपॉवर हो। टेस्ट, ट्रैक एवं ट्रीट पर विशेष फोकस रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाए। 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में टीकाकरण की गति में और तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के साथ कोविड पर नियंत्रण रखना होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव राधिका झा, अपर सचिव सोनिका, प्रो. दुर्गेश पंत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अब चला एमडीडीए का हथौड़ा : 32 अनाधिकृत निर्माण सील 27 बीघा भूमि में प्लॉटिंग ध्वस्त

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृजेश संत की सख्त कार्यवाही फील्ड में जारी है। एक तरफ सरकार का बुलडोज़र अवैध ज़मीनों पर लहलहाती इमारतों और कब्ज़ों पर दौड़ रहा है , वहीँ अब एमडीडीए का हथौड़ा भी कहर बन गया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृजेश संत द्वारा साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर रोक होनी चाहिए और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती से कार्यवाही की जाय।

इसी कर्म में प्राधिकरण ने बुधवार को सचिव मोहन सिंह वर्निया द्वारा दिए गए आदेशोंके बाद 32 अनाधिकृत निर्माणों को

सील एवं अवैध रूप से लगभग 27 बीघा भूमि में किये जा रहे प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। आपको क्रमवार बताते हैं कि देहरादून में एमडीडीए का हथौड़ा कहाँ कहाँ चला है -

1. वीरेंद्र सिंह कौशल द्वारा रानीपोखरी में भूतल पर 13 एवं प्रथम तल पर 13 दुकानों , कुल 26 दुकानों का निर्माण अवैध रूप से विना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था , जिसको सील कर दिया गया.

2. कुंदन सिंह बिष्ट द्वारा रानीपोखरी में तीन मंजिल पर 6 दुकानों का निर्माण अवैध रूप से विना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था , जिसको सील कर दिया गया.

3. चुन्नी लाल द्वारा ग्राम माजरी ग्रांट में लगभग 27 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति के भू विन्यास का कार्य किया जा रहा था , आदेश प्राप्त होने के पश्चात इस अवैध भू विन्यास को जे सी बी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया।

1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, ग्राहकों को मिलेंगे कई अधिकार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात कही है... यह बदलाव 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. इसके बाद ग्राहकों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे...

रिजर्व बैंक के अनुसार, नया नियम लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां अथवा बैंक को किसी भी ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले उससे अनुमति लेना जरूरी होगा... कार्ड को अपग्रेड करने से पहले भी ग्राहक की अनुमति जरूरी मानी जाएगी. .. अगर कंपनियां बिना ग्राहक की इजाजत के ही कार्ड जारी करती हैं या उसे अपग्रेड करती हैं तो उन्हें ग्राहक से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा....

आरबीआई ने कहा है कि नया नियम ग्राहकों को ज्यादा सक्षम बनाएगा और उनके पास कई अधिकार भी होंगे.... कंपनियां या बैंक कार्ड जारी कर या अपग्रेड करने के बाद अगर ग्राहक से शुल्क वसूलते हैं तो ग्राहक न सिर्फ इस शुल्क को चुकाने से इनकार कर सकते हैं, बल्कि संबंधित कंपनी या बैंक से जुर्माने की भी मांग कर सकते हैं... जुर्माने की राशि ग्राहक से वसूली जाने वाली फीस का दोगुना होगी...

मंत्री जी की बालियां, खेत में बजी तालियां, तस्वीर देख लोग बोले वाह !

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

विकासनगर से लौटते समय प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को अचानक जाने क्या सूझी और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और खुद खेतों में उतर गयी। कड़ी धुप में सुनहरे गेहूं के बालियों को काटते देख खुद मंत्री भी इस अभियान में जुट गयी। तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हुयी और अख़बारों की सुर्खियां बन गयी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केदारवाला में महिला किसानों के बीच हंसिया उठाई और गेहूं काटने लगी। एक पल को लगा ही नहीं कि वो कोई वीआईपी हैं और बड़ी कुशलता से काम को अंजाम भी दे दिया।

अपने बीच मंत्री जी को देख महिलाएं भी आश्चर्यचकित रह गईं.कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गेहूं की कटाई के साथ ही थ्रेसर पर गेहूं की मढ़ाई भी की... साथ ही खेतों में काम कर रहे महिलाओं से खेत की बुवाई से लेकर क्रय केंद्रों पर गेहूं व अन्य अनाज के विक्रय की जानकारी भी ली.... उन्होंने महिला किसानों से खेती में आने वाली समस्याओं को विस्तार से सुना... वहीं, महिलाओं से सस्ते गल्ले की दुकानों में सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन की भी जानकारी ली...

इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेत में मौजूद महिला किसानों को सम्मानित भी किया और कहा कि उनकी सरकार सदैव किसानों और महिलाओं के साथ खड़ी है....

चमोली पुलिस की तेज़ कार्यवाही से साइबर ठगी के शिकार की लौटी रकम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चमोली पुलिस की साइबर सेल ने एक बार फिर पहाड़ की जनता के मन में मित्र पुलिस के लिए भरोसे को और भी मजबूत किया है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे की अनुभवी लीडरशिप में टीम चमोली पुलिस लगातार अपराध पर ताबड़तोड़ कार्यवाही तो कर ही रही है साथ साथ जन सरोकार के मामलों में भी सबसे आगे नज़र आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर साइबर सेल की तेज़ कार्यवाही से ऑनलाइन ठगी के पीड़ित को उसकी रकम लौटा कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है।

आज के समय में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी श्वेता चौबे ने पहले ही अपनी टीम तैयार की है जिसको निर्देश दिए गए हैं कि चमोली में गठित साइबर सेल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें मिलते ही तेज़ी से कार्यवाही कर समाधान करते हुए पीड़ित को राहत दे। इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी साइबर- नताशा सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल बेहतरीन नतीजे दे रहा है। जन जागरूकता के चलते अब चमोली की आम जनता साइबर ठगी का शिकार होने पर सूचना साइबर सेल को दे रही है। एक घटना 20 अप्रैल

को सोनी देवी ग्राम मूसों गैरसैंण ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी , जिसमें उनके द्वारा जानकारी दी गयी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्धारा खुद को बाल विकास परियोजना अधिकारी बताकर उनका बच्चा होने पर उन्हें रू0 मिलने हैं जिसके लिए उन्हें अपनी निजी जानकारी साझा करने हेतु कहा गया जिसके पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा ओटीपी साझा किया गया जिसके पश्चयात वह साइबर ठगी का शिकार हो गये।

इस शिकायत पर साइबर सेल ने तेज़ कार्यवाही करते हुए संबंधित कंपनी से पत्राचार से तकनीकी मदद से उक्त व्यक्ति के खाते में शत प्रतिशत 32,000 रुपये वापस कराये गये। शिक़ायतकर्ता ने इसके बाद पुलिस को बताय कि उनके बैंक खाते में धनराशि ₹32,000 वापस आ गयी है। पीडित व्यक्ति द्धारा साईबर पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद किया । एसपी चमोली श्वेता चौबे भी लगातार आम नागरिकों को साइबर अपराद से बचने के लिए जागरूक कर रही हैं।इस दिशा में एक बार फिर चमोली पुलिस ने जन सामने से अपील की है -

चमोली एसपी श्वेता चौबे ने की आम जन से अपील --

- किसी अज्ञात व्यक्ति के कॉल और मैसेज से सावधान रहें।
- किसी को भी अपना Password, OTP,CVV शेयर ना करें।
- अंजान लिंक, ऑनलाइन जॉब्स ऑफर से सम्बंधित लिंक पर क्लिक ना करें।
- अंजान QR Code स्कैन ना करें।
- जागरूक बनें एवं अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करें।
- यदि कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो तत्काल नजदीकी थाना एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।

संपादकीय

नियम विरुद्ध कैद का हो समाधान

अपराधियों को कठोर दंड मिले, लेकिन बेगुनाह जेल में नहीं रहें. यह निर्विवाद तौर पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था है. संविधान के अनुच्छेद-21 में दिये गये जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्ण अय्यर ने 45 साल पहले एक अहम आदेश दिया था- सात साल से कम सजा के मामलों में जमानत (बेल) नियम और गिरफ्तारी (जेल) अपवाद होना चाहिए. अनुच्छेद-22 के तहत किसी व्यक्ति को अदालत के आदेश के बगैर 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता. सीआरपीसी कानून की धारा 167(2) के अनुसार जांच एजेंसी या पुलिस यदि दो या तीन महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलने का हक है. इसके बावजूद जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी भरे पड़े हैं. कैदियों को तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है. पहला, ऐसे मुजरिम, जिनकी सजा फाइनल हो गयी है. दूसरा, ऐसे अभियुक्त, जिनके मुकदमे का ट्रायल चल रहा है या अपील लंबित है. तीसरा, जिनकी एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो गयी, लेकिन जांच पूरी नहीं होने से आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ. विधि आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और मानवाधिकार संगठनों ने जेलों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कई रिपोर्ट दी, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा. इस मर्ज के लिए पुलिस और अदालतें दोनों जिम्मेदार हैं. गिरफ्तारी के बारे में दो तरह की कानूनी व्यवस्था है. पहला, संज्ञेय और गैरजमानती किस्म के गंभीर अपराध जैसे हत्या, लूट, बलात्कार और ड्रग्स आदि के मामलों में मजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है. दूसरे असंज्ञेय और जमानती किस्म के हल्के आपराधिक मामले. इनमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. यदि गिरफ्तारी जरूरी हो भी, तो थाने या अदालत से ही तुरंत जमानत मिलने और रिहाई के लिए कानूनी प्रावधान हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तीन साल से कम सजा के मामलों में बेवजह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. वर्ष 1994 में जोगिंदर कुमार के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के जज वेंकटचलैया ने बेवजह की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए जरूरी आदेश पारित किये थे. इनके अनुसार, शातिर अपराधी, जो नये अपराध करने के साथ गवाह और सबूत मिटा सकते हैं, उन मामलों में ही जमानत देने से इनकार होना चाहिए. गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की लोकसभा में पेश 230वीं रिपोर्ट के अनुसार, गलत एफआइआर या कानून के दुरुपयोग के मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सिविल मामलों में निचली अदालत, जिला अदालत और हाइकोर्ट का क्षेत्राधिकार निर्धारित होता है. लेकिन, क्रिमिनल मामलों में जिला अदालतों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी देने तक का असीमित अधिकार है. जज आरोपियों को जमानत देने में अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन से बचने की कोशिश करते हैं. इसकी वजह यह भी है कि अगर कोई निहित स्वार्थ या भ्रष्टाचार ना हो तो फिर आरोपियों को जमानत देकर जज बेवजह के विवादों में नहीं फंसना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में साफ किया है कि जेल भेजने के मामलों में मजिस्ट्रेट और जजों को विस्तृत और कानून सम्मत आदेश पारित करना चाहिए.

''फसल बीमा पाठशाला'' में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी - 380.29 करोड़ का क्लेम वितरित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, गणेश जोशी ने फ़सल बीमा योजना के तहत भारत सरकार के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित "किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी" कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस दौरान ''फसल बीमा पाठशाला'' का भी आयोजन किया गया।

भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव - भारत / 75 कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील भारत के 75 साल और भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को सेलिब्रेट करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सीधे किसानों तक पहुंचने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के अभियान को तेजी दी जा रही है। इसके तहत 25 अप्रैल से 1 मई तक बीमा कंपनियां चयनित ग्राम पंचायतों में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेंगी। ताकि किसानों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

कृषि मंत्री ने फसल बीमा पाठशाला के अवसर पर प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके कुशल निर्देश/नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य में भी ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में कृषि एवं औद्यानिक फसलों हेतु पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिनके मार्ग निर्देशन में उत्तराखण्ड राज्य में कृषि तथा औद्यानिक फसलों हेतु पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

■ फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष अब तक 3,61,075 कृषकों को रू0 380.29 करोड़ का क्लेम वितरित : कृषि मंत्री

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने बताया कि- उत्तराखण्ड राज्य में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 13 औद्यानिक फसलों यथा :- सेब, आम, लीची, आड़ू, माल्टा, सन्तरा, मौसमी, आलू, टमाटर, मटर, फ्रैन्चबीन, मिर्च एवं अदरक का बीमा किया जाता है। योजनान्तर्गत निर्धारित प्रीमियम में से 5 प्रतिशत कृषक अंश एवं शेष प्रीमियम का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 2 बीमा कम्पनियों का चयन किया गया है। जिनके माध्यम से कृषकों की फसलों का बीमा मौसम रबी एवं खरीफ में कराया जाता है। इन बीमा कम्पनियों के माध्यम से राज्य में स्थापित 118 मौसम केन्द्रों से विभिन्न मौसमी कारकों जैसेः- तापमान का घटना/बढ़ना, कम/अधिक वर्षा, ऑधी/तूफान आदि तथा फसल हेतु ओलावृष्टि को सम्मिलित कर फसलों को होने वाले नुकसान का आंकलन कर बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति क्लेम का वितरण किया जाता है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री द्वारा फसल बीमा पाठशाला में प्रतिभाग कर रहे समस्त बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों/विभिन्न जनपदों से आए राज्य के प्रतिनिधिक प्रगतिशील कृषक बन्धुओं का भी धन्यवाद दिया। इस दौरान सचिव कृषि, शैलेश बगौली, निदेशक कृषि गौरिशंकर, निदेशक बागवानी हरिमिंदर सिंह बावेजा बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि और किसान भी उपस्थित रहे।

सावधान : जस्ट डायल पर हो रहे बदनाम धंधे का हरिद्वार में हुआ खुलासा, एसओजी को सफलता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड को बदनाम करने वाला गंदा देह व्यापार का काला खेल हरिद्वार में ज़ोरों पर है। आये दिन यहाँ की गलियों और होटलों से बड़ी संख्या में सेक्स रैकेट से जुडी लडकियां पकड़ी जा रही हैं। ऐसे में लगता है देवभूमि की सबसे पवित्र नगरी सेक्स व्यापार की बदनाम राजधानी बनती जा रही है।

बुधवार सुबह उत्तराखंड पुलिस और एसओजी के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (SOG and Anti Human Trafficking Cell) की टीम ने हरिद्वार की पॉश कॉलोनियों में शुमार गोविंदपुरी के एक होटल में छापेमारी की... छापेमारी के दौरान बाहर से बुलाई गई चार कॉलगर्ल के साथ तीन युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है... आपको जानकर हैरानी होगी कि बदनामी की ये दुकान सीधे जस्ट डायल के माध्यम से चलाई जा रही थी। जस्ट डायल के द्वारा ही एक पूरा होटल लीज पर लेकर वहां पर सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था...

हरिद्वार में इन दिनों जस्ट डायल सेवा द्वारा होटलों में लड़कियां उपलब्ध कराने का काम जोरों शोरों से चल रहा है... इसके लिए बाकायदा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली फर्म हैं... ये फर्म अखबारों और मोबाइल पर अपने

विज्ञापन देती हैं... इनमें बाकायदा सुविधा देने वालों के फोन नंबर डाले होते हैं, जिनके माध्यम से ग्राहक इनसे सीधा संपर्क करते हैं... ग्राहकों को एक ही जगह पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह लोग उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं और यह सारा काम धड़ल्ले से जस्ट डायल के माध्यम से संचालित होता है... जस्ट डायल पर अपना नंबर देने वाले अलग-अलग जगहों पर एक पूरा होटल ही लीज पर लेते हैं और यहीं से अपने इस गंदे धंधे को संचालित करते हैं...

गलत धंधे में उपयोग हो रहे इस होटल का नंबर जस्ट डायल पर आसानी से सर्च हो रहा था. जिस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की नजर थी. जस्ट डायल पर इस तरह की सेवाएं लेने वालों को तत्काल यह नंबर नजर आ रहा था. हालांकि जस्ट डायल पर मसाज पार्लर और इससे जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही जाती थी, लेकिन अब यह तमाम लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं.पुलिस ने इस मामले में होटल से ही सेक्स रैकेट चलाने वाली उमा उर्फ पूजा निवासी दिल्ली के साथ तीन अन्य युवतियां व तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसने से एक कनखल व एक ज्वालापुर का रहने वाला बताया जा रहा है...

भाईचारे की मिसाल बने सुहेल खंडवानी व दिलशाद खान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुंबई। माहिम दरगाह/हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी ने पूरे महाराष्ट्र से काफी लोगों को माहिम में एक साथ जमा किया। इस दौरान सुहेल खंडवानी ने कहा कि पवित्र रमजान एक प्रशिक्षण का महीना है, जो रोजेदारों को बुराइयों से बचने की सीख देता है। उन्होंने कहा कि रमजान समाज में भाईचारे और समरसता की सीख देता है। साथ ही आपस में भाईचारे की बात करते हुये देश में अमन शांती की सभी से अपील की। सुहेल खंडवानी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक व सम्मानित शख्सियतों से अपील करते हुये कहा कि आप सब अपने-अपने क्षेत्र में अमन शांती बनाये रखें, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आपस में सभी को लड़ाकर भाईचारा खत्म कराना चाहते हैं लेकिन हम ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस दौरान माहिम में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया और सभी रोजेदारों ने अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में हाथ उठाकर मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी।

इस कार्यक्रम में हिंदु, मुस्लिम, सीख, ईसाई सभी समाज के बड़े-बुजर्ग व नौजवानों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों, समुदाय के धार्मिक नेताओं, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ कई सम्मानित शख्सियत शामिल हुए, जिन्होंने देश की विकास और सभी समुदायों की समृद्धि के लिए राष्ट्रीय पहल में सांप्रदायिक सद्भाव की प्रासंगिकता पर चर्चा की।

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री व मुंबई शहर के पालकमंत्री असलम शेख, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, विधायक वारिस पठान, विधायक अमीन पटेल, विधायक जीशान सिद्दीकी, विधायक रईस शेख, जगदीश सिंह छपरा, नगरसेवक मोसिन भाई, नगरसेवक नजीर मुल्ला, दै. मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद खान, सुरज सिंह ठाकुर, इमरान बाबू कुरैशी, खालिद बाबु कुरैशी, फारूख घीवाला, माहिम क्षेत्र के डीसीपी प्रणय अशोक, अर्शी मिर्जा, शाकिब माहिमी, आसिफ दादरकर, तनवीर मर्चेंट, सलीम मापखन, अरशद भाई, मोईन अजमेरी, डॉ. मुदस्सिर लांबे, बिजनेसमैन सुरेश कामा, मोहम्मद इब्राहिम शेख, फिरोज सामा, साजिद सुपारीवाला, जावेद पारिख, दाऊद खान सहित कई जाने माने लोग तशरीफ लाये थे। दै. मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद खान ने बताया कि रमजान-उल-मुबारक का यह पाक व पवित्र महीना रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदार को इफ्तार कराता है अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है।

यूपी बोर्ड की कॉपी में इश्क़ का इज़हार और नोट देख गुरु जी हैरान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर देश भर के स्टूडेंट को मोटिवेट करते हो , ताकि परीक्षा में वह बेहतर जवाब लिख सकें ... लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के पन्ने देखेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे ... बीते कई दशकों से यूपी बोर्ड देश में चर्चा का विषय रहा है ... कहा जाता है यूपी बोर्ड का बड़ा बच्चा सबसे काबिल और होशियार होता है और अगर उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो कहना ही क्या .. लेकिन हुजूर ज़रा ठहरिये ... सच्चाई इतनी ही नहीं है।

बीते कई सालों से यूपी बोर्ड की कॉपियों में जिस तरह से छात्रों द्वारा हास्यास्पद और विवादास्पद ऑफिस लिखे जाते रहे हैं वह आज की युवा पीढ़ी की सोच को दर्शाने के लिए काफी है। यूपी बोर्ड की कॉपियां अलग-अलग जिलों में युद्ध स्तर पर जांच की जा रही है और पारदर्शिता के साथ टीचर इस काम को कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद से लेकर मेरठ तक और गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक जिन स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं उन्होंने कॉपी में पास कराने के लिए तरह-तरह के ऑफर भी दिए हैं। जी हां मार्केटिंग प्रोडक्ट को बेचने के ऑफर की तरह बेफिजूल के जवाबों के बदले शानदार नंबर की डिमांड करते हुए छात्रों ने तरह-तरह के प्रलोभन कॉपी में लिखकर गुरु जी को दिए हैं। जिसमें शादी का बहाना , माताजी की बीमारी , आर्थिक स्थिति का खराब होना और पैसे देकर लालच की आड़ में नंबर पाना जैसा हथकंडा शामिल है। सबसे चौंकाने वाला मसला तो अपने कच्चे प्यार का इज़हार भी लड़के उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं। ऐसा सिर्फ यूपी बोरड़ में होता है हम नहीं कहते लेकिन यूपी बोर्ड के चर्चे सस्बे ज्यादा होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

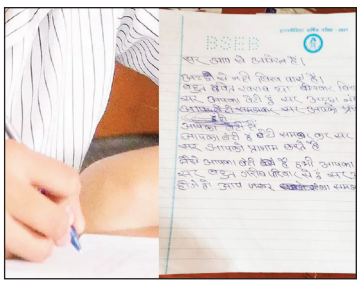

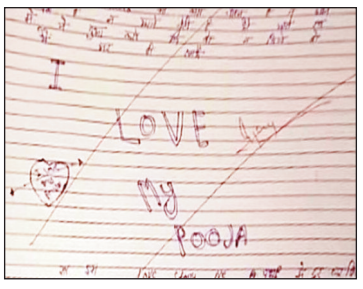

आजकल यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके.... शिक्षक कॉपियों के जांचने का अपना टार्गेट पूरा कर रहे हैं.... ऐसे में कुछ कॉपियां ऐसी मिल रही हैं जिनमें लिखा कुछ नहीं है बस मास्टर साहब से विनती की गई है..... ऐसी ही एक कॉपी में विद्यार्थी ने बाकयदा अपना मोबाइल नम्बर लिखा हुआ है.... साथ ही लिखा है मास्टर साहब पास कर दो बाकी गूगल पे कर दूंगा....

शिक्षकों ने बताया कि यही नहीं कई कॉपियों में बाकयदा नोटभी बाँध कर रखे जाते हैं ताकि लालच दिया जा सके। कई छात्राओं ने अपनी पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए शिक्षकों से इमोशनल अपील की है....लेकिन इससे कोई फर्क गुरूजी पर नहीं पड़ता है बल्कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। ये आज भी सच्चाई है कि युवा पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर कहीं कहीं कितने गैर ज़िम्मेदार रवैया अपना रहे हैं जिस बारे में न सिर्फ अध्यापकों को बल्कि अभिभावकों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए।

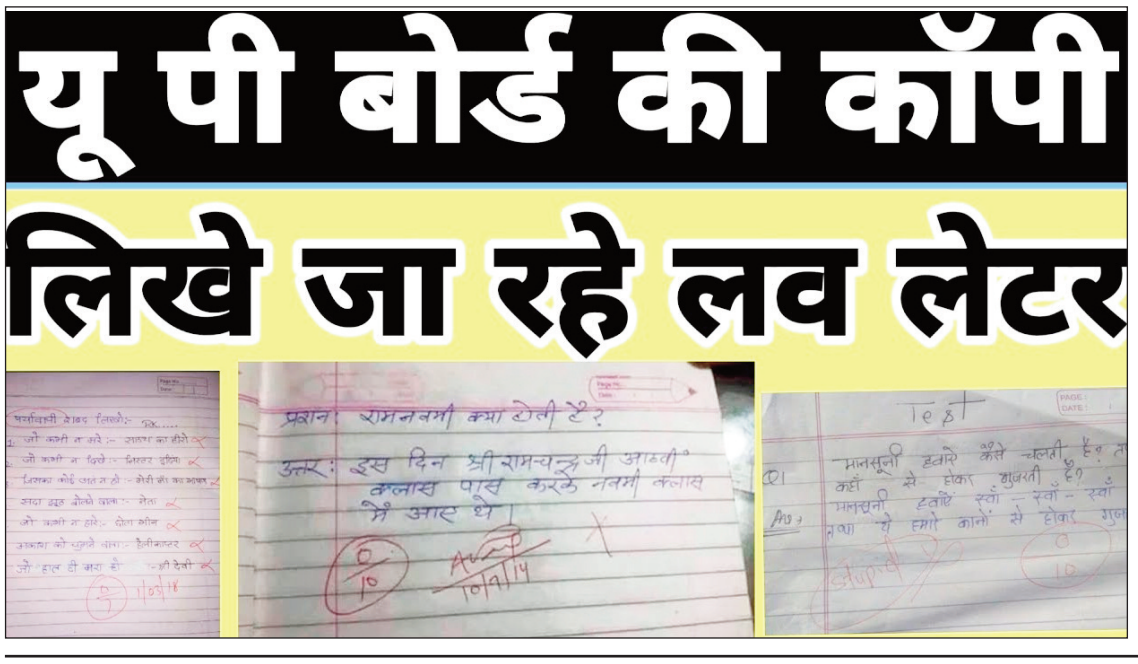

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज देहरादून में, ये है कार्यक्रम

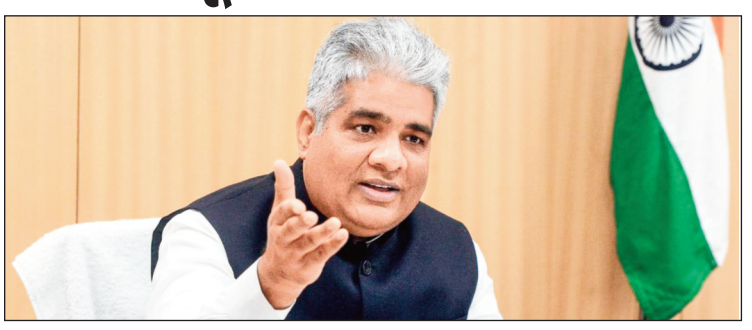

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज देहरादून में हैं। केंद्रीय मंत्री का ये दो दिन का दौरा है कार्यकर्म के मुताबिक वन मंत्री यादव एफआरआई और डब्ल्यूआईआई में कई बैठकों में भाग लेंगे पहुंचे हैं । जिसमें वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन ,नई फारेस्ट पालिसी सहित कई अहम विषयों पर वे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा वनमन्त्री प्रोजेक्ट एलिफेंट,प्रोजेक्ट डालफिन पर भी बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे।

आईजीएनएफए में नए बने स्वीमिंग पूल का भी वे उद्घाटन किया जाना है । वे एफएसआई के आधुनिक लैब का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही उसमें इस्तेमाल हो रही नई तकनीकों की भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा हिमालयन इकोलॉजी पर भी विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। डब्ल्यूआईआई का विश्व स्तरीय संस्थान बनाने को लेकर भी वे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। राज्य वन विभाग के अधिकारी भी उनसे मुलाकात करेंगे।

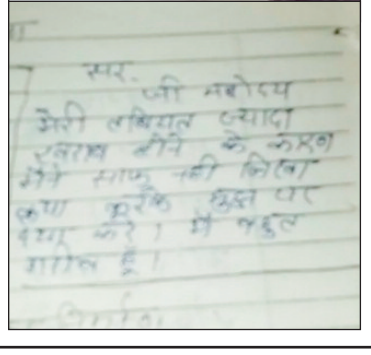

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा